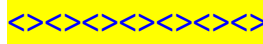
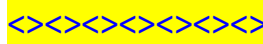




- सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी आपत्ति के बाद एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान पुस्तक के वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
- इजरायल की संसद, नेसेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित किया।
- दक्षिण अंडमान जिले की दिशा बैठक आयोजित—जिला उपायुक्त ने सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
- कला एवं संस्कृति निदेशालय की ओर से 2 मार्च को होगा फाग उत्सव का आयोजन।



सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संदर्भों पर कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद—एनसीईआरटी ने पुस्तक के वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और इसे निर्णय में त्रुटि बताते हुए खेद व्यक्त किया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एनसीईआरटी ने कहा कि कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' के खंड—दो प्रकाशित किए जाने के बाद, यह पाया गया कि अध्याय चार, 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका'—, में कुछ अनुचित पाठ्य सामग्री और निर्णय संबंधी त्रुटियां अनजाने में शामिल हो गईं।



इजरायल की संसद, नेसेट ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित किया। नेसेट अध्यक्ष अमीर ओहाना ने यरुशलम में सांसदों को संबोधित करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी को पदक प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं, जिन्हें यह सम्मान मिला है। सम्मान को प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि भारत और इजरायल के बीच अटूट मित्रता को समर्पित है। नेसेट प्रशस्ति पत्र में रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि, नवाचार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।



आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थान की दो श्रेणियों में दिया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च है। पात्र व्यक्ति और संस्थान राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।



द्वीप समूह के दौरे पर आए DANICS प्रोबेशनर्स के 62वें बैच के 11 अधिकारियों के एक समूह ने कल लोक निवास में एडमिरल डी के जोशी से भेंट की। द्वीप समूह में अपना तीन महीने का कार्यकाल पूरा करने वाले इन प्रोबेशनर्स से उपराज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव मांगे, जिसमें पर्यटन, मत्स्य पालन, ब्लू इकोनॉमी, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा उप-राज्यपाल ने अधिकारियों से अंडमान बेसिन में किए जा रहे तेल अन्वेषण कार्यों पर भी अपने विचार साझा करने को कहा। उप-राज्यपाल ने उनके द्वारा दिए गए सुझावों को द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से संचालित द्वीप प्रशासन की मेगा परियोजनाओं में शामिल करने का निर्देश दिया।



सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की ओर से द्वीप समूह में नाइट सी कायाकिंग के संचालन को विनियमित करने के लिए मसौदा दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इसका उद्देश्य द्वीप समूह में रात के समय समुद्री कायाकिंग के सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन के लिए नियम बनाना है। इन मसौदा दिशा-निर्देशों को आम जनता, पर्यटन हितधारकों और विभिन्न विभागों से सुझाव, टिप्पणियाँ और इनपुट के लिए निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। सभी टिप्पणियाँ, सुझाव, और इनपुट निर्धारित प्रारूप में भरकर 12 मार्च तक निदेशालय में जमा किए जा सकते हैं। प्रासंगिक और रचनात्मक पाए जाने वाले इनपुट को दिशा-निर्देशों के अंतिम संस्करण में शामिल किया जाएगा।



दक्षिण अंडमान जिले की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति- दिशा की बैठक कल आपदा प्रबंधन विभाग में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद श्री बिष्णु पद रे ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार, द्वीप प्रशासन और स्थानीय निकायों की भूमिकाओं के संवैधानिक ढांचे के भीतर विकासात्मक पहलों की निगरानी में सुधार करना था। बैठक के दौरान सांसद ने दक्षिण अंडमान की

विकासात्मक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सहयोगात्मक शासन और सरकारी योजनाओं को समय पर लागू करने के महत्व पर जोर दिया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग ने सभी विभागों को सांसद द्वारा किए गए अवलोकनों और उनके द्वारा सुझाई गई कार्रवाइयों पर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट जमा न करने वाले किसी भी विभाग के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।



कला एवं संस्कृति निदेशालय की ओर से 2 मार्च को फाग उत्सव के साथ रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। कार्यक्रम अंडमान क्लब में शाम 6 बजे से आरंभ होगा। इस अवसर पर गैर सरकारी संगठन पंख के सहयोग से "होली के पकवान" नामक एक विशेष पारंपरिक पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में लोकप्रिय पारंपरिक मिठाइयाँ और उत्सव के व्यंजन तैयार करने होंगे। इच्छुक प्रतिभागी 28 फरवरी तक कला एवं संस्कृति निदेशालय में रोहित राज से संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम में पारंपरिक लोक और भक्ति संगीत का प्रदर्शन, लाइव होली गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ तथा पारंपरिक होली व्यंजनों का प्रदर्शन शामिल हैं।



बाल विकास परियोजना अधिकारी, रंगत कार्यालय ने ICDS रंगत के तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के खाली पड़े पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 09 मार्च शाम 5 बजे तक अपना आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, रंगत में जमा कर सकते हैं। साक्षात्कार रंगत और मायाबंदर के पंचायत समिति प्रमुख के कक्ष में आयोजित किया जाएगा। इस पद के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज क्षेत्र के मूल निवासी हैं। योग्यता, मानदेय, पात्रता मानदंड और आवेदन के प्रारूप की विस्तृत जानकारी समाज कल्याण निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।



भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, की ओर से 12 दिवसीय 'फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी' पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके समापन अवसर पर मुख्य अतिथि ANCCI के अध्यक्ष डॉ. के. चंद्रशेखरन ने उभरते हुए उद्यमियों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान केन्द्रशासित

प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति के मुख्य प्रबंधक पी. के. उम्मर फारूक ने नगरपालिका क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के साथ स्ट्रीट वेंडर के रूप में पंजीकरण करने की सलाह दी। संस्थान के निदेशक सी. राज ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान लगभग 36 प्रकार के व्यंजन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, बैंक जमा और ऋण योजनाओं, तथा साइबर धोखाधड़ी के बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस प्रशिक्षण में विभिन्न क्षेत्रों की 34 बेरोजगार महिलाओं ने भाग लिया।

